



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 27, 2008/आश्विन 5, 1930

No. 529]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 27, 2008/ASVINA 5, 1930

कार्यिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2008

साकानि. 692(अ).—केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित आगे और नियम दबाती है, अर्थात्:

- (1) इन नियमों का नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2008 है।  
 (2) अन्यथा उपबंधित किसी बात को छोड़कर, ये 1 जनवरी, 2006 को लागू हुए समझे जाएंगे सिवाय अनुसूची 11-ग और 'घ' में विहित केन्द्रीय (कार्यवाधि पर प्रतिनियुक्ति) भते के प्रावधानों को छोड़कर जो कि 1 सितम्बर, 2008 से लागू होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम-2 में (जिसे यहां उपर्युक्त नियमावली के रूप में संदर्भित किया गया है) —  
 (i) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:  
 '(क क) संशोधित वेतन ढांचे में "मूल वेतन" से अभिप्राय है निर्धारित पेय बैंड में आहरित वेतन और लागू ब्रेंड-पे लेकिन इसमें विशेष वेतन इत्यादि जैसा कोई और वेतन शामिल नहीं है।

(एच.ए.जी.+और शीर्षस्थ वेतनमान के वेतनमान में सेवा के सदस्य के मामलों में मूल वेतन से अभिप्राय है, निर्धारित वेतनमान का वेतन;

(ii) खण्ड (ड.) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(ड.) “ग्रेड-पे” पूर्व-संशोधित वेतनमान अथवा पदों के तदनुरूपी नियम राशि है;

(iii) खण्ड (अ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

‘(अ क) “पे-बैंड में वेतन” से अभिप्राय है नियम 3 के उप-नियम-1 में विनिर्दिष्ट रनिंग पे-बैंडों में आहरित वेतन;

(iv) खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

‘(ड क) “संशोधित परिलक्षियाँ” से अभिप्राय है पे-बैंड में वेतन और संशोधित वेतन ढांचे में सेवा के सदस्य की ग्रेड-पे अथवा शीर्षस्थ वेतनमान और मंत्रिमण्डल सचिव के वेतनमान में मूल वेतन;

‘(ड ख) अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी पद के सम्बन्ध में “संशोधित वेतन ढांचे” से अभिप्राय कॉलम-5 और 6 में विनिर्दिष्ट उस पद अथवा वेतनमान पर विनिर्दिष्ट पे-बैंड अथवा ग्रेड-पे से है जब तक कि उस पद के लिए एक अलग संशोधित पे-बैंड और ग्रेड-पे अथवा वेतनमान अलग से अधिसूचित नहीं कर दिया जाता;

3. उपर्युक्त नियमावली के नियम-3 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) पे-बैंड और ग्रेड-पे – सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय पे-बैंड और ग्रेड-पे और वे तारीख जिनसे पे-बैंड और ग्रेड-पे लागू हुए समझे जाएंगे, निम्नानुसार होंगे:-

(क) कनिष्ठ वेतनमान –

पे-बैंड – 3: 15600-39100 रुपये और ग्रेड-पे 5400 रुपये ।

## (ख) वरिष्ठ वेतनमान :-

- (i) वरिष्ठ समय वेतनमान — पे-बैंड — 3: 15600-39100 रुपये और ग्रेड-पे 6600 रुपये
- (ii) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड — पे-बैंड — 3: 15600-39100 रुपये और 7600 रुपये ग्रेड-पे ।
- (iii) चयन ग्रेड:- पे-बैंड — 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 8700 रुपये ग्रेड-पे ।

## (ग) अधिसमय वेतनमान :-

- (i) पुलिस उप-महानिरीक्षक  
पे-बैंड — 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 8900 रुपये ।
- (ii) पुलिस महानिरीक्षक  
पे-बैंड-4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 10000 रुपये ।

## (घ) अधिसमय वेतनमान से ऊपर के वेतनमान :-

- (i) पुलिस अपर महानिदेशक —  
पे-बैंड — 4: 37400-67000 रुपये और ग्रेड-पे 12000 रुपये ।
- (ii) ए.ए.जी.प्लस: 75500 रुपये (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) —  
80000 रुपये; ग्रेड-पे: शून्य
- (iii) शीर्षस्थ वेतनमान: 80000 रुपये (नियत) और ग्रेड-पे: शून्य  
पुलिस महानिदेशक के मौजूदा एक पद का प्रत्येक राज्य संवर्ग में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में उन्नयन ।  
(भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2008 की अधिसूचना के जारी होने की तिथि से लागू)

टिप्पणी 1. — समय वेतनमान और इससे ऊपर के पदों पर सेवा के सदस्य की नियुक्ति, भारतीय पुलिस सेवा में विभिन्न ग्रेडों में पदोन्नति के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार विनियमित की जाएगी :

बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य भारतीय पुलिस सेवा(भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम-6क के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरी करने के पश्चात् वरिष्ठ समय वेतनमान में, 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में, 13 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् चयन ग्रेड में, 14 वर्ष की सेवा पूरी

करने के पश्चात् पुलिस उप महानिरीक्षक अधिसमय वेतनमान में तथा 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् महानिरीक्षक अधिसमय वेतनमान में नियुक्त किए जाने का पात्र हो जाएगा ।

बशर्ते आगे यह भी कि सेवा का कोई सदस्य विनिर्दिष्ट अनिवार्य मध्य केरिअर प्रशिक्षण चरण-III पूरा करने के पश्चात् ही कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा ।

टिप्पणी 2. शीर्षस्थ वेतनमान में पुलिस महानिदेशक का पद 75500 (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) – 80000 रुपये के एच.ए.जी.+वेतनमान – राज्य संवर्ग के पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा भरा जाएगा ।

टिप्पणी 3. जब कभी राज्य अथवा संयुक्त संवर्ग का भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी पे-बैंड-3 में अथवा पे-बैंड-4 की विशिष्ट ग्रेड-पे के ग्रेड में केन्द्र में तैनात किया जाता है तो सेवा के सदस्य, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों से 2 वर्ष या इससे अधिक वरिष्ठ हों और अभी तक उस ग्रेड विशेष में पदोन्नत नहीं किए गये हों, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के उस अधिकारी की उस ग्रेड विशेष में तैनाती की तिथि से गैर-कार्यात्मक आधार पर उसी ग्रेड में नियुक्त किए जाएंगे ।

टिप्पणी 4. इस नियम में सेवा के 4 वर्ष, 9 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्षों की गणना, भारतीय पुलिस सेवा (वरिष्ठता का विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-3 के अंतर्गत इसे आबंटित, आबंटन वर्ष से की जाएगी ।

टिप्पणी 5. चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार के अलावा ली गई किसी असाधारण छुट्टी अथवा सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा सुविधारित, सेवा के सदस्य के नियंत्रण से परे किसी कारण के लिए ली गई छुट्टी अथवा अध्ययन के लिए ली गई छुट्टी जो कि लोकहित में हो और जिसके लिए अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) विनियमावली, 1960 के अंतर्गत अध्ययन छुट्टी अन्यथा अनुशेय हो, की अवधि को इन ग्रेडों में नियुक्ति के लिए अपेक्षित सेवा की पात्रता अवधि की गणना करने के आशय से शामिल नहीं किया जाएगा ।

बशर्ते यह कि सेवा का कोई सदस्य उस तारीख तक मौजूदा वेतनमान में वेतन आहरित करते रहने का विकल्प दे सकता है जिस तारीख को वह मौजूदा वेतनमान में

अपनी अगली या कोई तदनुरूपी वेतनवृद्धि पाता है अथवा जब तक वह अपना पद छोड़ देता है अथवा जब तक वह उस वेतनमान में वेतन आहरित करना बंद कर देता है:

बशर्ते यह कि ऐसे मामलों में जहां सेवा के सदस्य को 1 जनवरी, 2006 और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच में पदोन्नति अथवा वेतनमान के अपग्रेडेशन के कारण उच्चतर वेतनमान में रखा गया है, सेवा के सदस्य ऐसी पदोन्नति अथवा अपग्रेडेशन, जैसा भी मामला हो, की तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प दे सकते हैं।

**स्पष्टीकरण 1-** इन नियम के परन्तुक के अन्तर्गत मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा वेतनमान के मामले में देय होगा।

**स्पष्टीकरण 2-** उपर्युक्त विकल्प 1 जनवरी, 2006 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन ढांचे में ही वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

**स्पष्टीकरण 3-** जहां सेवा का कोई सदस्य उस वेतनमान में वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न क्षमता पर धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अन्तर्गत मौजूदा वेतनमान को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह भूलभूत वेतन होगा जो मौजूदा वेतनमान के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका पुनर्व्यवस्थापन किया जाए तक उसका पुनर्व्यवस्थापन किया जाए तो वह वेतन इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की खासियत लिए हुए वह अर्जित करता।

4. नियम-4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:

‘4. संशोधित वेतन ढांचे में वेतन का निर्धारण - सेवा का कोई सदस्य जो इन नियमों के अनुसार, 1 जनवरी, 2006 को अथवा बाद की किसी तारीख को संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार विकल्प देता है अथवा विकल्प दिया हुआ समझा जाता है तो उसके आरंभिक वेतन का, उसके उस स्थायी पद, जिस पर उसका पुनर्व्यवस्थापन किया जाए है और वह पद जिस पर उसका पुनर्व्यवस्थापन किया जाए हो यदि वह निम्नवित न हो गया होता, के वास्तविक वेतन के अनुसार उस

तारीख से अलग से पुनः निर्धारित किया जाएगा और उसके द्वारा धारित पद स्थानापन्न वेतन के संबंध में निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा अर्थात् :-

(क) सेवा के सभी सदस्यों के मामलों में:-

- (i) वेतन बैंड अथवा वेतनमान में वेतन का निर्धारण 1 जनवरी, 2006 को यथाविद्यमान भौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अंगते गुणज में पूर्णकित करके किया जाएगा ।
- (ii) यदि संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान का न्यूनतम उपर्युक्त (i) के अनुसार प्राप्त राशि से ज्यादा है तो वेतन संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा ।

बास्तव कि

(क) वेतन निर्धारण में जहां कहीं सेवा के किसी सदस्य का वेतन जो भौजूदा वेतनमान में दो या अधिक संयोजी अवस्थाओं पर आहरित वेतन समूहबद्ध हो जाता है अर्थात् अन्यथा कहीं तो इसी अवस्था पर संशोधित वेतन ढांचे में वेतन बैंड में निर्धारित हो जाता है तो इस प्रकार से समूहबद्ध ऐसी प्रत्येक दो अवस्थाओं के लिए उन्हें एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा जिससे कि संशोधित रनिंग वेतन बैंडों में दो अवस्थाओं से अधिक बंचिंग से बचा जा सके । इस प्रयोजन के लिए वेतन वृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर परिकलित की जाएगी और बंचिंग को कम करने के लिए वेतनवृद्धियां देते समय वेतन बैंड को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त ढंग से वेतन वर्धन से यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन बैंड अथवा वेतनमान (जहां-कहीं लागू हो) की उस अवस्था पर

निर्धारित हो जाता है जो कि अगली उच्च अवस्था अथवा अवस्थाओं वाले संशोधित वेतन बैंड वाले कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है, तब ऐसी स्थिति में बाद वाले कर्मचारी का वेतन उस सीमा तक बढ़ाया जाएगा जब तक कि वह पिछले कर्मचारी के वेतन की तुलना में कम हो;

(iii) वेतन बैंड में वेतन उपर्युक्त तरीके से निर्धारित होगा और वेतन बैंड में वेतन के अलावा मौजूदा वेतनमान के अनुरूप शेड वेतन भी देय होगा ।

(ख) सेवा के उस सदस्य, जो भारत के बाहर 1 जनवरी, 2006 को प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा पर था अथवा जो उच्चतर पद पर कार्य करने के अलावा एक या अधिक निम्नतर पदों पर उस तारीख को कार्य कर रहा होता, के मामले में “विद्यमान वेतनमान” में, उस पद जिस परं वह उच्चतर पद पर कार्य करने के अलावा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी अथवा विदेश सेवा अथवा, जैसा भी मानला हो, के लिए लागू वेतनमान शामिल है ।

(ग) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि मौजूदा वेतनमान में वेतन के अलावा विशेष वेतन अथवा भत्ता ले रहे हैं तथा जिनके लिए स्थानापन्न तौर पर किसी विशेष वेतन अथवा भत्तों के बिना ही कोई वेतन बैंड और शेड वेतन दिया गया है, ऐसे सदस्यों का वेतन संशोधित वेतन ढांचे में उपर्युक्त उप खण्ड (क) में निहित प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा ।

(घ) सेवा के उन सदस्यों के मामले में जो कि वर्तमान वेतनमानों में मिल रहे वेतन के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से विशेष वेतन घटक प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि छोटे परिवार के मानकों को प्रोत्साहन देने के लिए व्यक्तिगत वेतन, केल्ड्रीय ( कार्यकाल पर प्रतिनियुक्ति ) भत्ता, आदि तथा जिनके मामले में इनके स्थान पर साहश्य भत्ता अथवा वेतन के साथ संशोधित वेतन ढांचा लागू कर लिया गया है, के मामले में संशोधित वेतनमान उपर्युक्त धारा (क) के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित होंगे और ऐसे मामलों में संस्तुत नई दरों पर भत्ते, इन

भत्तों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट तारीख से संशोधित वेतन ढांचे में मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मिलेंगे ।

**टिप्पणी 1-** निलंबनाधीन सेवा का सदस्य वेतन के विधमान वेतनमान पर आधारित निर्वाह भत्ता लेता रहेगा और संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन लंबित अनुशासनिक कार्यवाहियों पर अन्तिम आदेश के अध्यधीन होगा ।

**टिप्पणी 2-** सेवा के किसी सदस्य की “मौजूदा परिलिंग्यां” संशोधित परिलिंग्यों से अधिक हो जाती है तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

**स्पष्टीकरण-** इस टिप्पणी के उद्देश्य के लिए, “मौजूदा परिलिंग्यां” से अभिप्राय (i) मौजूदा मूल वेतन (ii) मूल वेतन पर उपयुक्त मंहगाई वेतन और (iii) मूल वेतन पर मंहगाई भत्ता + औसत सूचकांक 536(1982=100) पर मंहगाई वेतन की कुल जमा राशि ।

**टिप्पणी 3-** जहां उप नियम (1) के अधीन वेतन निर्धारण में सेवा का कोई सदस्य जो मौजूदा वेतनमान में 1 जनवरी, 2006 के तुरंत पहले समान केंडर के किसी कनिष्ठ कर्मचारी की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन बैंड में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन बैंड में उसी अवस्था में बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ कर्मचारी हो ।

**टिप्पणी 4-** जहां सेवा का कोई सदस्य 1 जनवरी, 2006 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो खण्ड (क) अथवा (ख) के अनुसार उसकी मौजूदा परिलिंग्यों से जुड़ने पर संशोधित परिलिंग्यों से अधिक हो जाता है, तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों के रूप में सेवा के किसी सदस्य के व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

**टिप्पणी 5-** उस सेवा के सदस्य के मामले में जो 1 जनवरी, 2006 के पूर्व “हिन्दी शिक्षण योजना” के अन्तर्गत हिन्दी प्राज्ञ और ऐसी अन्य

परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा है, उनका यह व्यक्तिगत वेतन, संशोधित वेतन संरचना में भूल वेतन के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाएगा, वे 1 जनवरी, 2006 से या उससे आगे की अवधि के लिए संशोधित वेतन ढांचे में उस व्यक्तिगत वेतन को प्राप्त करते रहेंगे जो कि वे संशोधित वेतन ढांचे का निर्धारण न होने की दशा में प्राप्त करते। ऐसा व्यक्तिगत वेतन, निर्धारण की तिथि से संशोधित वेतन ढांचे में वेतन वृद्धि की उचित दर से उस अवधि तक के लिए दिया जाएगा जिस अवधि तक अधिकारी उसे प्राप्त करना जारी रखता।

**स्पष्टीकरण :** इस टिप्पणी के प्रयोजन के लिए “संशोधित वेतन ढांचे में वेतनवृद्धि की उपयुक्त दर” का तात्पर्य वेतन बैंड में वेतन के कुल के 3 प्रतिशत के बराबर धनराशि तथा उस स्तर पर ग्रेड वेतन है जिस पर कर्मचारी का वेतन, संशोधित वेतन ढांचे में नियत किया गया है।

**टिप्पणी 6 -** जहां दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया सेवा का कोई ज्येष्ठ सदस्य अपने कनिष्ठ सदस्य से पुनरीक्षित वेतनमान में कम वेतन प्राप्त करता है, जो 01 जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात उच्चतर पद पर पदोन्नत किया गया है वहां सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन बैंड में वेतन को उस उच्चतर पद में उसके कनिष्ठ सदस्य के वेतन बैंड में नियत किए गए वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जाएगा और वेतन के बढ़ाए (स्टेप-अप) जाने को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के आधारीन सेवा के कनिष्ठ सदस्य की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी किया जाएगा अर्थात् :-

- सेवा के कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों सदस्य उसी काडर के होंगे और वह पद जिन पर उन्हें पदोन्नत किया गया है उसी काडर में सदृश होंगे;
- निम्नतर और उच्चतर पदों के पूर्व संशोधित वेतनमान और संशोधित ग्रेड वेतन जिसमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, एक-समान होंगे;

- (ग) पदोन्नति के समय सेवा का ज्येष्ठ सदस्य कनिष्ठ के बराबर या अधिक वेतन पा रहा हो और;
- (घ) विषमता, इस टिप्पणी के उपबंधों के लागू करने के परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः होगी।

(ड.) यहां तक कि यदि निम्नतर पद में कनिष्ठ अधिकारी उसको अनुदत्त किन्हीं अग्रिम वेतनवृद्धियों के कारण ज्येष्ठ व्यक्ति से पूर्व संशोधित वेतनमान में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था, तो इस टिप्पणी के प्रावधानों को सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन को बढ़ाने के लिए विखंडित किए जाने की आवश्यकता है।

**टिप्पणी 7:-** उपरोक्त उपबंधों के अनुसरण में सेवा के ज्येष्ठ सदस्य के वेतन में पुनः नियतन से संबंधित आदेश सुसंगत नियमों के अधीन जारी किया जाएगा और सेवा का ज्येष्ठ सदस्य वेतन के पुनः नियतन की तारीख से उसके द्वारा अपेक्षित सेवा पूरी करने पर अगली वेतनवृद्धि का हकदार होगा।

(ड.) दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण- जहां सेवा का कोई सदस्य मौजूदा वेतनमान में वेतन आहरित करना जारी रखता है और 01 जनवरी, 2006 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतन ढांचे का विकल्प देता है तो संशोधित वेतन ढांचे में उसका वेतन, बाद वाली तारीख से इन्हीं नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए मौजूदा वेतनमान में उसका वेतन खंड (क), (ग) अथवा (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार यथा परिकलित मौजूदा परिलब्धियों के मामले के बराबर होगा, परन्तु इस शर्त के अध्यधीन कि बाद वाली तारीख में मूल वेतन और जहां सेवा का सदस्य सेवा विशेष भूत्ता प्राप्त कर रहा है, उसका वेतन इस प्रकार परिकलित परिलब्धियों के उपर्युक्त संशोधित दरों पर विशेष भूत्ते के समान धनराशि की उन परिलब्धियों में से घटाकर नियत किया जाएगा।

## 5. उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 में :-

- (क) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“सीधी अर्ती के अधिकारी का प्रारंभिक वेतन, 5400 रुपए के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा;

बशर्ते कि यदि सीधी अर्ती का कोई अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उस पर लागू नियमों के तहत लियन रखता है, अथवा लियन रखता यदि उसका लियन स्थायी आधार पर निर्भवित न कर दिया गया होता, उसका आरंभिक वेतन निम्नलिखित तरीके से विनियमित किया जाएगा अर्थात्:-

- (क) वह, परिवीक्षा की अवधि के दौरान स्थायी पद का वेतन आहरित करेगा, यदि यह कनिष्ठ वेतनमान और भारतीय पुलिस सेवा में स्थायीकरण होने पर उसके वेतनमान के न्यूनतम से अधिक है;
- (ख) यदि वह भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी समूह 'क' के पद को धारण किए हुए था, उसका वेतन, उस स्तर पर निर्धारित किया जाएगा जैसा कि वेतन बैंड-3 जमा ग्रेड वेतन 5400 में समूह 'क' के लिए किया जाएगा; और
- (ग) यदि वह समूह 'क' से किसी निम्नतर पद को धारण किए हुए था तो उसका वेतन, वेतन बैंड-3 में निम्नतर पद में वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि देकर और ऐसे निम्नतर पद के लिए अनुज्ञेय ग्रेड वेतन देकर संगणित तथा 10 के अगले गुणज तक पूरा करके नियत किया जाएगा। तथापि, यदि यह वेतन, वेतनवृद्धि जोड़कर वेतन बैंड-3 के न्यूनतम वेतन से कम है तो उसका वेतन, वेतन बैंड-3 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा,
- (घ) तथापि, कनिष्ठ वेतनमान में वह कोई वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि अपनी सेवा अवधि के हिसाब से वह किसी उच्चतर वेतन के लिए पात्र नहीं बन जाता।

परन्तु यह और कि वह नियम 9 के तहत अनुज्ञेय वेतन आहरित करेगा, यदि वह पूर्ववर्ती परन्तुक में उल्लिखित वेतन से अधिक है।”

- (ख) उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(2) वरिष्ठ समय वेतनमान के पद पर पदोन्नत होने पर कनिष्ठ वेतनमान के सेवा के सदस्य का वेतन संशोधित वेतन द्वाये में निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा :

वेतन बैंड और मौजूदा ग्रेड-पे के कुल वेतन के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि तथा 10 के अगले गुणज तक पूरा किया जाएगा । इसे वेतन बैंड के शुरू के मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जाएगा । इसके पश्चात् वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नति पद की तदनुरूपी ग्रेड-पे दी जाएगी ।”

(ग) उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4) कनिष्ठ पुलिस ग्रेड में नियुक्ति होने पर वरिष्ठ समय वेतनमान में सेवा के सदस्य का वेतन बैंड-3 में उसी प्रकार निर्धारित किया जाएगा जैसे कि उप-नियम (2) में उपर्युक्त अनुसार वेतन बैंड-3 के मौजूदा वेतन में 7600 रुपये का ग्रेड वेतन जोड़कर किया जाता है

(घ) उप नियम (5) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को पदस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(5) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के सेवा के सदस्य की चयन ग्रेड में पदोन्नति होने पर उसका वेतन पे-बैंड-4 में और यदि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के सदस्य द्वारा आहरित वेतन पे-बैंड 3 में पे-बैंड 4 के न्यूनतम से कम है तो इसे पे-बैंड 4 के न्यूनतम पर निर्धारित किया जाएगा तथा उन्हें चयन ग्रेड में 8700 रुपये का ग्रेड-पे दिया जाएगा”;

(ङ.) उप नियम (6) के लिए निम्नलिखित उप नियम पदस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(6) सेवा के सदस्य की प्रथम अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर चयन ग्रेड में द्वितीय अधिसमय वेतनमान में नियुक्ति होने पर प्रथम अधिसमय वेतनमान में अथवा अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में नियुक्ति होने पर द्वितीय अधिसमय वेतनमान में अथवा

एच.ए.जी.+में पदोन्नति होने पर अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में वेतन का निर्धारण, उप-नियम (2) में दिए तरीके से किया जाएगा और पे-बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त द्वितीय अधिसमय वेतनमान अथवा अधिसमय वेतनमान से ऊपर का प्रथम वेतनमान, जैसा भी मामला हो, के अनुसार तदनुरूपी ग्रेड वेतन दिया जाएगा ।

(च) उप-नियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

“(6क) अधिसमय वेतनमान से ऊपर के द्वितीय वेतनमान अर्थात् एच.ए.जी.+वेतनमान में नियुक्ति होने पर अधिसमय वेतनमान से ऊपर के प्रथम वेतनमान में सेवा के सदस्य का वेतन निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :-

उप-नियम 2 में निर्धारित तरीके के अनुसार एक वेतनवृद्धि जोड़कर पे-बैंड के वेतन में मौजूदा ग्रेड-पे जोड़ दी जाएगी और परिणामी राशि एच.ए.जी.+ में मूल वेतन बन जाएगी । वह इस वेतनमान के अधिकतम अर्थात् 80000 रुपये से अधिक नहीं हो ।

(छ) उप नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“सेवा में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नत होने पर सेवा के सदस्य के पास विकल्प होगा कि वह अपना वेतन, उच्चतर पद के पे-बैंड में या तो अपनी पदोन्नति की तारीख से या उस वर्ष की पहली जुलाई से निर्धारित करा सके, जब वह उपर्युक्त संगत उप-नियम में किए गए प्रावधान के अनुसार निचले ग्रेड में तदनुरूप बाद की वेतनवृद्धि अर्जित करता है । बाद वाले मामले में, पदोन्नति की तिथि को पे-बैंड में वेतन, निचले पद के समान ही निर्धारित किया जाएगा परन्तु ग्रेड-पे उच्चतर पद की ही होगी तथा इसका पुनर्निर्धारण संबंधित उप-नियमावली में किए गए प्रावधान के अनुसार एक जुलाई, जो निचले वेतनमान में वास्तविक वेतनवृद्धि की तिथि है, से किया जाएगा ।”

6. उक्त नियमावली के नियम-6 में -

(i) उप नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(1)(क) इन नियमों के नियम 6 या नियम 7 के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के अध्यधीन भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 7 या नियम 7क के अन्तर्गत नियुक्त सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष की पहली जुलाई को एक-समान रूप से दी जाएगी।

(ख) संशोधित वेतन ढांचे में एक जुलाई को 6 माह या इससे अधिक पूरा करने वाले अधिकारी 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार, वेतनवृद्धि पाने के पाव्र होंगे।

(ग) संशोधित वेतन ढांचे में 1 जनवरी, 2006 को वेतन निर्धारण के पश्चात् पहली वेतनवृद्धि दिनांक 1 जुलाई, 2006 को, सेवा के उन सदस्यों को दी जाएगी जिनकी वेतनवृद्धि की अगली तिथि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच थी।

(घ) सेवा के सभी सदस्य जिन्होंने अपनी अन्तिम वेतनवृद्धि 1 जनवरी, 2005 तथा 1 जनवरी, 2006 के बीच अर्जित की थी, वे अपनी वेतनवृद्धि 1 जुलाई, 2006 को अर्जित करेंगे।

बशर्ते कि उन व्यक्तियों के मामलो में, जो 01 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मौजूदा वेतनमान के अधिकतम पर थे, उन्हें संशोधित वेतन ढांचा में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2006 से दी जाएगी, उसके बाद यह नियम लागू होगा :

बशर्ते यह भी कि यदि सेवा का सदस्य जहाँ अपने वेतन बैंड के अधिकतम पर पहुँच जाता है, वह उस अधिकतम पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में आ जाएगा। उसे उच्चतर वेतन बैंड में रखे जाने के समय, उसे एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा, उसके बाद उसके उस वेतन बैंड-4 के अधिकतम पर पहुँचने तक वह उच्चतर वेतनबैंड में घलता रहेगा, जिसके बाद उसे कोई अगली वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।

- (ii) उप-नियम (2) और (3) का लोप कर दिया जाएगा;
- (iii) “वेतनमान” और “वेतन बैंड” शब्दों के लिए उप-नियम (6) में “वेतन बैंड और बैंड वेतन” शब्द प्रतिस्थापित होंगे;

7. उपर्युक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात् :-

“7 संशोधित वेतन ढांचा में वेतनवृद्धि की दर -

- (1) संशोधित वेतन ढांचा में वेतनवृद्धि की दर, लागू वेतन बैंड और बैंड वेतन में वेतन की राशि के 3% के बराबर होगी, जो 10 की गुणा पर पूर्ण होगी तथा उस वेतनवृद्धि राशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ा जाएगा।
- (2) वेतन बैंड-3 के मामले में, 3% और 4% पर वेतनवृद्धि की अलग-अलग दरें दी जाएं।
- (3) वेतनवृद्धि की उच्चतर दर, वेतन बैंड-3 में अधिकारियों की पद संख्या के 20% से अधिक को नहीं दी जाएगी।”

8. उपर्युक्त नियमों के नियम 8 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होंगे :-

“(9) - भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 13 में विहित किसी भी बात के बावजूद राज्य सरकार सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त उम्मीदवार द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा अथवा सेवा की अवधि की अनदेखी करते हुए परीक्षाएं, जिनके पश्चात् वह पे-बैंड में निर्धारित दर पर वेतन आहरित करने का हकदार हो जाएगा, परीक्षा पास करने के पश्चात् वेतनवृद्धि की निर्धारित तिथि से उसे देय दूसरी ओर तीसरी वेतनवृद्धि स्वीकृत करेगी।

बशर्ते कि इस नियम के अंतर्गत तीसरी वेतनवृद्धि, निर्धारित विभागीय परीक्षा, या अंतिम निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने और स्थायीकरण पर जैसी भी स्थिति हो, वेतनवृद्धि की निर्धारित तारीख से पूर्व-प्रभावी दी जाएगी :

बशर्ते कि यह भी कि सीधी भर्ती किए गए कोई व्यक्ति, जिसे पूरी विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं या विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं का किसी भाग में, जैसी भी

स्थिति हो, इस कारण से उपस्थित होने से छूट दी गई है, कि उसने, सेवा का सदस्य होने से पूर्व, ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं या उनके किसी भाग को पहले ही उत्तीर्ण कर लिया है, को, इस नियम के प्रयोजनार्थ, उस पूर्व परीक्षा या परीक्षाओं या उनके भाग, जिनमें वह उपस्थित होता, की तारीख के बाद विभागीय परीक्षा या परीक्षाओं या उनके भाग, जैसी भी स्थिति हो, को उत्तीर्ण किया गया माना जाएगा, लेकिन छूट के लिए, सेवा का सदस्य होने के बाद”।

9. उपर्युक्त नियमों के नियम 11 में, उप-नियम (7) में, “24050-650-26000 रुपए” अक्षरों और अंकों के स्थान पर “75500 रुपये (वार्षिक वेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) – 80000 रुपये” अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित होंगे।
10. उपर्युक्त नियमों की अनुसूची-। में,

(क) “01 जनवरी, 1996” अंक, अक्षर और शब्द जहाँ-कहीं ये आते हैं के स्थान पर “01 जनवरी, 2006” अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित होंगे;

(ख) पैरा (1) के लिए, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“(1) नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रथम उपबंध तथा उसके अंतर्गत टिप्पणियों में किसी बात के होते हुए, पदोन्नत अधिकारी या चयन द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, का आरंभिक वेतन, निम्नलिखित तरीके से अधिकारी की पात्रता के अनुसार वरिष्ठ वेतनमान के तीन घटकों के लिए अनुज्ञेय एक ग्रेड वेतन के अतिरिक्त राज्य सेवा में वेतन बैंड-3 या वेतन बैंड-4 में अधिकारी द्वारा आहरित वेतन पर नियत किया जाएगा, अर्थात् :-

<u>वेतन बैंड में वेतन</u>	ग्रेड- पे
वेतन बैंड-3 में 28280 रुपए तक के वेतन में अधिकारी	6600/-
वेतन बैंड-3 में 28281 रुपए से 30690 रुपए के मध्य वेतन में अधिकारी	7600/-
वेतन बैंड-3 अथवा वेतन बैंड-4 में 30691 रुपए अथवा उससे ऊपर के वेतन में अधिकारी	8700/-

यदि राज्य सेवा में अधिकारी का वेतन 1 जनवरी, 2006 से नए वेतन ढांचे के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है, इसे नियम 4 में समाविष्ट प्रावधानों के आधार पर संशोधित किया जाएगा ।

11. उक्त नियमों की अनुसूची-II के, निम्नलिखित राज्यों में 75500/- (वार्षिकवेतनवृद्धि 3 प्रतिशत की दर से) - 80,000/- रुपये के एच.ए.जी.वेतनमान में पुलिस महानिदेशक 80,000 (नियत) के शीर्ष वेतनमान में रखा जाएगा और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में पुलिस बल के प्रमुख के रूप में निम्नानुसार पदनामित किया जाएगा, अर्थात् :-

राज्य	पदनाम	शीर्ष वेतनमान
(1)	(2)	(3)
आंध्र प्रदेश	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
टिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
आसाम	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
मेघालय	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
बिहार	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
छत्तीसगढ़	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
गुजरात	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
हरियाणा	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
हिमाचल प्रदेश	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
जम्मू और कश्मीर	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
झारखण्ड	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
कर्नाटक	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
केरल	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
मध्य प्रदेश	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
महाराष्ट्र	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
मणिपुर	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
त्रिपुरा	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
नागालैण्ड	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)

पंजाब	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
उड़ीसा	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
राजस्थान	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
तमिलनाडु	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
उत्तराचल	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
उत्तर प्रदेश	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)
पश्चिम बंगाल	पुलिस महानिदेशक (सेना पुलिस शीर्ष)	80,000/- रुपये (नियत)

12. उक्त नियमों की अनुसूची-11-क और 11-ग में,

(क) “वेतन अथवा वेतनमान” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“वेतन अथवा वेतनमान अथवा वेतन बैंड+ग्रेड वेतन”

(ख) “26000 रुपये”, “24050-650-26000 रुपये”, “22400-525-24500 रुपये”, “18400-500-22400 रुपये”, “16400-450-20000 रुपये” अक्षर, अंक और शब्द जहां-कहीं ये आते हों के स्थान पर “80000 रुपये”, “75500-(वार्षिक वेतनबृद्धि 3 प्रतिशत की दर से ) - 80000 रुपये”, “वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपये जमा ग्रेड वेतन 12000 रुपये”, “वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपये जमा ग्रेड वेतन 10000 रुपये”, “वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपये; जमा ग्रेड वेतन 8900 क्रमशः अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।”

13. अनुसूची-11-ग में, :-

(क) महानिदेशक, भारत-तिष्वत सीमा पुलिस के पद से सम्बन्धित कॉलम (4) के अंतर्गत क्रम संख्या-6 पर दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“80000 रुपये (नियत)”;

(ख) क्रम सं. 12 के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“12.क सशस्त्र सीमा बल – महानिदेशक – 80000 रुपये (नियत)”;

(ग) 'केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता' से सम्बद्ध कॉलम (5) के अंतर्गत 1000 रुपये, 800 रुपये और 400 रुपये अक्षर और अंक जहां-कहीं आते हों, के स्थान पर "अधिकतम चार हजार रुपये प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) अनुसूची-1-ग के अंत में आने वाली टिप्पणी-1 और टिप्पणी-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'टिप्पणी:- इस नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता सेवा के किसी सदस्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए दिया जाएगा।'

14. अनुसूची-1 के अंतर्गत "11.घ-सेवा के सदस्य द्वारा धारित केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद और तालिका" के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"11.घ-सेवा के सदस्य द्वारा धारित केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पद

#### तालिका

पद का नाम	वेतनमान	केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भत्ता
(1)	(2)	(3)
(1) भारत सरकार के सचिव/भारत सरकार के विशेष सचिव	8000/- रुपए (नियत)	---
(2) भारत सरकार के अपर सचिव	वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपए; और घेड वेतन 12000 रुपए	---
(3) भारत सरकार के संयुक्त सचिव	वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपए; और घेड वेतन 10000 रुपए	---
(4) भारत सरकार के निदेशक	चयन घेड (वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपए; और घेड वेतन 8,700/- रुपए)	अधिकतम चार हजार रुपए प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत
(5) भारत सरकार के उप सचिव	चयन घेड: (वेतन बैंड-4: 37400-67000 रुपए; और घेड वेतन	अधिकतम चार हजार रुपए प्रति मास के

	8,700/- रुपए) या  कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: वेतन बैंड- 3: 15600-39100 रुपए; और ग्रेड वेतन 7600 रुपए	अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत
(6) भारत सरकार के अवर सचिव	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड: वेतन बैंड- 3: 15600-39100 रुपए; और ग्रेड वेतन 7600 रुपए या  वरिष्ठ समय वेतनमान (ग्रेड: वेतन बैंड-3: 15600-39100 रुपए; और ग्रेड वेतन 6600 रुपए	अधिकतम चार हजार रुपए प्रति मास के अध्यधीन मूल वेतन का दस प्रतिशत

टिप्पणी 1 – इस नियम में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय (पदावधि पर प्रतिनियुक्ति) भल्ता, सेवा के किसी सदस्य को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए दिया जाएगा”।

[फा. सं. 14021/4/2008-अ.भा.से.(II)]

हरजोत कौर, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि.सं. 108(इ.), तारीख 21 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### व्याख्यात्मक जापन

केन्द्रीय सरकार ने यथा अनुमोदित संशोधन के अनुसार भारत सरकार के दिनांक 29 अगस्त, 2008 के संकल्प सं. 1/1/2008-आईसी में यथा विहित अखिल भारतीय सेवाओं के वेतनमानों में संशोधन के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 से कार्यान्वित करने का निर्णय किया है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के महेनजर, भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 को 1 जनवरी, 2006 से तदुसार संशोधित किया जा रहा है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से भारतीय पुलिस सेवा के किसी भी सदस्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2008

G.S.R. 692(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2008.
  - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, except the provisions of Central (Deputation on Tenure) Allowance, contained in Schedule II-'C' & 'D' which shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of September, 2008..
2. In rule 2 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules),—
  - (i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—
 

‘(aa) “basic pay” in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed pay band plus the applicable grade pay but does not include any other type of pay like special pay, etc.

In the case of members of the Service, in the HAG+ and the apex scale, basic pay means the pay in the prescribed scale;’;
  - (ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:—
 

‘(e) “grade pay” is the fixed amount corresponding to the pre-revised pay scale or posts;’;
  - (iii) after clause (j), the following shall be inserted, namely :—
 

‘(ja) “pay in the pay band” means pay drawn in the running pay bands specified in sub-rule (1) of rule 3;’;
  - (iv) after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely :—
 

‘(ka) “revised emoluments” means the pay in the pay band plus the grade pay of a member of the Service in the revised pay structure or the basic pay in the Apex scale and the Cabinet Secretary’s scale;’;

‘(kb) “revised pay structure” in relation to any post specified in Schedule II means the pay band and grade pay specified against that post or the pay scale specified in column 5 and 6 thereof, unless a different revised pay band and grade pay or pay scale is notified separately for that post;’;
3. In rule 3 of the said rules, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—
  - “(1) Pay-Bands and Grade Pays. - The pay bands and grade pays admissible to a member of the Service and the dates with effect from which the said pay bands and grade pays shall be deemed to have come into force, shall be as follows:—
    - A. Junior Scale—  
Pay-Band – 3: Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs.5400;

**B. Senior Scale -**

- (i) **Senior Time Scale-** Pay-Band – 3: Rs.15600-39100 plus Grade Pay Rs.6600.;
- (ii) **Junior Administrative Grade –**  
Pay-Band – 3: Rs.15600-39100; plus Grade Pay Rs.7600;
- (iii) **Selection Grade :-**  
Pay-Band – 4: Rs.37400-67000; plus Grade Pay Rs.8700;

**C Super Time Scale :**

- (i) **Deputy Inspector General of Police –**  
Pay-Band – 4: Rs.37400-67000; plus Grade Pay Rs.8900;
- (ii) **Inspector General of Police –**  
Pay-Band – 4: Rs.37400-67000; plus Grade Pay Rs.10000;

**D Above Super Time Scale -**

- (i) **Additional Director General of Police –**  
Pay-Band – 4: Rs.37400-67000; plus Grade Pay Rs.12000;
- (ii) **HAG + :** Rs.75500- (annual increment @ 3%)-80000 ;  
Grade Pay : nil;
- (iii) **Apex Scale :** Rs.80000 (fixed), Grade Pay : nil (by upgradation of one existing post of Director General of Police as head of police force in the each State cadre):  
(with effect from the date of issue of notification of the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2008);

**Note 1:** Appointment of a member of the Service to the Senior Time Scale and above shall be regulated as per the provisions in the Guidelines regarding promotion to various grades in the Indian Police Service.

Provided that a member of the Service shall be eligible for appointment to the Senior Time Scale on his completion of four years of service, subject to the provisions of sub-rule 2 of rule 6A of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, to the Junior Administrative Grade on completion of nine years of service, to the Selection Grade on completion of thirteen years of service, to the Deputy Inspector General Super Time Scale on completion of fourteen years of service and to the Inspector General Super Time Scale on completion of eighteen years of service.

Provided further that a member of the service shall be appointed to the Junior Administrative Grade only after he has completed phase III mandatory Mid Career Training as specified by the Central Government.

**Note 2:** The post of Director General of Police in the apex scale shall be filled by selection from amongst the officers holding the post of Director General of Police in the State cadre in the HAG+ scale of Rs.75500-(annual increment @ 3%)- 80000.

**Note 3:** Whenever any Indian Administrative Service officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in pay band 3 or pay band 4, the members of Service, who are senior to such Indian Administrative Service officer by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade, shall be appointed to the same grade

on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service officer in that particular grade.

**Note 4:** The four years, nine years, thirteen years, fourteen years and eighteen years of service in this rule shall be calculated from the year of allotment assigned under rule 3 of the Indian Police Service (Regulation of Seniority) Rules, 1954.

**Note 5:** The period of extraordinary leave taken otherwise than on medical certificate or considered by the State Government concerned to have been taken for any cause beyond the control of the member of the Service or for prosecuting studies, which are in public interest and for which Study Leave could otherwise be admissible under the All India Service (Study Leave) Regulations, 1960, shall be excluded for the purpose of calculating the eligibility period of service required for appointment in these grades:

Provided that a member of Service may opt to continue to draw pay in the existing scale until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing scale or until he vacates his post or ceases to draw pay in that scale;

Provided further that in cases where a member of the Service has been placed in a higher pay scale between 1<sup>st</sup> day of January, 2006 and the date of notification of these Rules on account of promotion or upgradation of pay scale etc., the member of Service may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be.

**Explanation 1.** - The option to retain the existing scale under the proviso to this rule shall be admissible only in respect of one existing scale.

**Explanation 2.** - The said option shall not be admissible to any person appointed to the Service on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 and he shall be allowed pay only in the revised scale.

**Explanation 3.** - Where a member of the Service exercises an option under the proviso to this rule to retain the existing scale in respect of a post held by him in an officiating capacity on a regular basis for the purpose of regulation of pay in that scale, his substantive pay shall be the substantive pay which he would have drawn had he retained the existing scale in the permanent post on which he holds lien or would have held a lien had his lien not been suspended or the pay of the officiating post which has acquired the character of substantive pay in accordance with any order for the time being in force whichever is higher.”.

4. for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:-

‘4. Fixation of pay in the revised pay structure. - The initial pay of a member of the Service who opts or deemed to have opted in accordance with these rules, to be governed by the revised scale on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 or from a later date, which shall be re-fixed as from that date separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds a lien or would have held a lien if it had not been suspended, and in respect of his pay in the officiating post held by him, in the following manner, namely:-

(A) in the cases of all members of the Service,-

- (i) the pay in the pay band or pay scale shall be determined by multiplying the existing basic pay as on 1<sup>st</sup> day of January, 2006 by a factor of 1.86 and rounding off the resultant figure to the next multiple of 10;
- (ii) if the minimum of the revised pay band or pay scale is more than the amount arrived at as per (i) above, the pay shall be fixed at the minimum of the revised pay band or pay scale;

Provided that -

- (a) where, in the fixation of pay, the pay of a member of the Service drawing pay at two or more consecutive stages in an existing scale gets bunched, that is to say, gets fixed in the revised pay structure at the same stage in the pay band, then, for every two stages so bunched, benefit of one increment shall be given so as to avoid bunching of more than two stages in the revised running pay bands. For this purpose, the increment shall be calculated on the pay in the pay band and the grade pay would not be taken into account for the purpose of granting increments to alleviate bunching;
- (b) if by stepping up of the pay as above, the pay of a member of the Service gets fixed at a stage in the revised pay band or pay scale (wherever applicable) which is higher than the stage in the revised pay band at which the pay of a member of the Service who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former;
- (iii) the pay in the pay band shall be determined in the above manner and in addition to the pay in the pay band, grade pay corresponding to the existing scale shall be payable.

- (B) In the case of a member of the Service, who was on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 on deputation out of India or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in a higher post, the "existing scale" includes the scale applicable to the post which he would have held but for his being on deputation out of India or on leave or on foreign service or, as the case may be, but for his officiating in a higher post.
- (C) In the case of members of the Service who are in receipt of special pay or allowance in addition to pay in the existing scale which has been recommended for replacement by a pay band and grade pay without any special pay or allowance, pay shall be fixed in the revised pay structure in accordance with the provisions of clause (A) above.
- (D) In the case of members of the Service who are in receipt of special pay component with any other nomenclature in addition to pay in the existing scales, such as personal pay for promoting small family norms, Central (Deputation on Tenure) Allowance, etc., and in whose case the same has been replaced in the revised pay structure with corresponding allowance or pay at the same rate or at a different rate, the pay in the revised pay structure shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) above and in such cases, the allowance at the new rate as recommended shall be drawn in addition to pay in the revised pay structure from the date specified in the individual notifications related to these allowances.

**Note 1** - A member of the Service under suspension, shall continue to draw subsistence allowance based on existing scale of pay and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

**Note 2** - Where the "existing emoluments" exceed the revised emoluments in the case of any member of Service, the difference shall be allowed as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

**Explanation.**— For the purpose of this Note, “existing emoluments” mean the sum of (i) existing basic pay, (ii) dearness pay appropriate to the basic pay and (iii) dearness allowance appropriate to the basic pay + dearness pay at index average 536 (1982=100).

**Note 3** -Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a member of the Service, who, in the existing scale was drawing immediately before the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 more pay than another member of the Service junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay band at a stage lower than that of such junior, his pay shall be stepped upto the same stage in the revised pay band as that of the junior.

**Note 4** -Where a member of the Service is in receipt of personal pay on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, which together with his existing emoluments in accordance with clause (A) or (B), as the case may be, exceeds the revised emoluments, then, the difference representing such excess shall be allowed to such member of the Service as personal pay to be absorbed in future increases in pay.

**Note 5** -In the case of members of the Service who are in receipt of personal pay for passing Hindi Pragya and such other examinations under the “Hindi Teaching Scheme” prior to the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, while the personal pay shall not be taken into account for purposes of fixation of initial pay in the revised pay structure, they would continue to draw personal pay after fixation of their pay in the revised pay structure on and from the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 or subsequently for the period for which they would have drawn it but for the fixation of their pay in the revised pay structure. The quantum of such personal pay would be paid at the appropriate rate of increment in the revised pay structure from the date of fixation of pay for the period for which the officer would have continued to draw it.

**Explanation** - For the purpose of this Note, “appropriate rate of increment in the revised pay structure” means 3% of the sum of the pay in the pay band and the grade pay at the stage at which the pay of the employee is fixed in the revised pay structure.

**Note 6** -In cases where a senior member of Service promoted to a higher post before the 1<sup>st</sup> day of January, 2006 draws less pay in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher post on or after the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, the pay in the pay band of the senior member of Service should be stepped up to an amount equal to the pay in the pay band as fixed for his junior in that higher post the stepping up should be done with effect from the date of promotion of the junior member of Service subject to the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (a) both the junior and the senior members of Service should belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted should be identical in the same cadre;
- (b) the pre-revised scale of pay and the revised grade pay of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay should be identical;
- (c) the senior member of Service at the time of promotion should have been drawing equal or more pay than the junior;
- (d) the anomaly should be directly as a result of the application of the provisions of this Note.
- (e) If even in the lower post, the junior officer was drawing more pay in the pre-revised scale than the senior by virtue of any advance increments granted to him, provisions of this rule need not be invoked to step up the pay of the senior member of the Service.

**Note 7 :** The order relating to re-fixation of the pay of the senior member of the Service in accordance with the above provisions shall be issued under the relevant rules and the senior member of the Service shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.

(E) Fixation of pay in the revised scale subsequent to 1<sup>st</sup> day of January, 2006 - Where a member of Service continues to draw his pay in the existing scale and opts for revised pay structure from a date later than the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed under these rules and for this purpose his pay in the existing scale shall be the same as of existing emoluments as calculated in accordance with clause (A), (C) or (D), as the case may be, subject to the condition that the basic pay on the later date and where the member of the Service is in receipt of special allowance, his pay shall be fixed after deducting from those emoluments an amount equal to the special allowance at the revised rates appropriate to the emoluments so calculated.'

5. In rule 5 of the said rules,

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"The initial pay of a direct recruit shall be fixed at the minimum of Pay-Band-3 with Grade Pay of Rs.5400:

Provided that, if a direct recruit holds a lien, or would hold the lien, had his lien not been suspended on permanent post, under the rules applicable to him prior to his appointment to the Indian Police Service, his initial pay shall be regulated in following manner, namely:-

(a) he shall, during the period of probation, draw the pay of the permanent post, if it is more than the minimum of the Junior Scale and on confirmation in the Indian Police Service;

(b) if he was holding a Group A post before appointment to the Indian Police Service, his pay shall be fixed at the same stage as the pay in the Group A post in the Pay-Band-3 plus Grade Pay Rs.5400; and

(c) if he was holding a post lower than a Group A post, his pay in Pay Band-3 shall be fixed as the pay arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by one increment equal to 3% of the sum of the pay in the pay band and the grade pay admissible for such lower post, computed and rounded off to the next multiple of 10. However, if the pay in the pay band after adding the increment is less than the minimum of the pay band-3, pay in the pay band shall be fixed at the minimum of pay band-3.

(d) he shall, however, cease to earn any increments in the Junior Scale, until, having regard to his length of service, he becomes entitled to a higher pay:

Provided further that he shall draw the pay admissible under rule 9 if that is more than the pay referred to in the preceding proviso.";

(b) for sub-rule (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The pay of a member of the Service in the Junior Scale shall, on appointment to a post in the Senior Time Scale, be fixed in the revised pay structure as follows:

One increment equal to 3% of the sum of existing pay in the pay band and the existing grade pay shall be computed and rounded off to the next multiple of 10. This shall be added to the existing pay in the pay band. Thereafter, grade pay

corresponding to the promotion post shall be granted in addition to this pay in the pay band”;

(c) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(4) The pay of a member of the Service in the Senior Time Scale shall, on appointment to the Junior Administrative Grade, be fixed in pay band-3 fixed in the manner provided in sub-rule (2) plus the grade pay of Rs.7600”;

(d) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The pay of a member of the Service in the Junior Administrative Grade shall, on appointment in the Selection Grade, be fixed in pay band-4 and in case the pay drawn by the member of Service in Junior Administrative grade in pay band 3 is less than the minimum of pay band 4, it shall be fixed at the minimum of pay band 4 and the grade pay of Rs.8700 shall be granted to the Selection Grade.”;

(e) for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:-

“(6) The pay of a member of the Service in the Selection Grade, on appointment to the 1<sup>st</sup> Super Time Scale or in the 1<sup>st</sup> Super Time Scale, on appointment to the 2<sup>nd</sup> Super Time Scale or in the 2<sup>nd</sup> Super Time Scale on appointment to the 1<sup>st</sup> Above Super Time Scale, shall be fixed in the manner provided in sub-rule (2) and the grade pay corresponding to the 1<sup>st</sup>, 2<sup>nd</sup> Super Time Scale or 1<sup>st</sup> Above Super Time Scale, as the case may be, shall be granted in addition to this pay in the pay band.;

(f) after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely :-

“(6a) The pay of a member of the Service in 1<sup>st</sup> Above Super Time Scale, on appointment to 2<sup>nd</sup> Above Super Time Scale i.e. HAG+, shall be fixed in the following manner, namely:-

After adding one increment in the manner prescribed in sub-rule 2, the pay in the pay band and existing grade pay will be added and the resultant figure will become the basic pay in HAG+. This shall not exceed Rs. 80,000, the maximum of the scale.;

(g) for sub-rule (7), the following shall be substituted, namely:-

“(7) On promotion from one grade to another in the Service, a member of the Service shall have an option to get his pay fixed in the Pay Band of the higher post either from the date of his promotion or from the 1<sup>st</sup> day of July of the year, the date on which he subsequently earns an increment in the lower grade in the manner provided in the relevant sub-rule above; in the latter case, on the date of promotion pay in the pay band shall be fixed as the same in the lower post but the grade pay shall be that attached to the higher post, with further re-fixation to be done in the manner provided in relevant sub-rules with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, the date of accrual of the next increment in the lower scale.”;

6. In rule 6 of the said rules,

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) (a) Subject to any order passed by the State Government concerned, under rule 6 or rule 7, the increment admissible to a member of the Service appointed under rule 7 or rule 7A of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, shall accrue uniformly on the 1<sup>st</sup> July of every year;

(b) Officers completing six months and above in the revised pay structure as on the 1<sup>st</sup> day of July shall be eligible to be granted the increment;

(c) The first increment after fixation of pay on the 1<sup>st</sup> day of January 2006 in the revised pay structure shall be granted on the 1<sup>st</sup> day of July 2006 for those members of the Service for whom the date of next increment was between the 1<sup>st</sup> July, 2006 to the 1<sup>st</sup> day of January, 2007.

(d) All members of the Service who earned their last increment between 1<sup>st</sup> day of January 2005 and 1<sup>st</sup> day of January 2006 shall get their increment on the 1<sup>st</sup> day of July 2006:

Provided that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing scale for more than a year as on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006, the next increment in the revised pay structure shall be allowed on the 1<sup>st</sup> day of January, 2006. Thereafter, this rule shall apply:

Provided further that in cases where a member of Service reaches the maximum of his pay band, shall be placed in the next higher pay band after one year of reaching such a maximum. At the time of placement in the higher pay band, benefit of one increment shall be provided, thereafter, he shall continue to move in the higher pay band till his pay in the pay band reaches the maximum of PAY BAND-4, after which no further increments shall be granted.”;

- (ii) Sub-rule (2) and (3) shall be omitted;
- (iii) In sub-rule (6), for the words “scale of pay” and “grade of pay”, the words “pay band and grade pay” shall be substituted;

7. For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“7. Rate of increment in the revised pay structure. —

- (1) The rate of increment in the revised pay structure shall be 3% of the sum of the pay in the pay band and grade pay applicable, which shall be rounded off to the next multiple of 10 and the amount of increment shall be added to the existing pay in the pay band.
- (2) In the case of pay band-3, variable rates of increment at 3% and 4% have been provided.
- (3) The higher rate of increment shall be granted to not more than 20% of the strength of officers in pay band-3.”

8. For rule 9 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-

“9. Notwithstanding anything contained in rule 13 of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the State Government shall sanction the second and third increments due to a direct recruit with effect from the prescribed date of increment after he passes the prescribed departmental examination or examinations irrespective of the length of service, after which he shall be entitled to draw pay at the prescribed rate in the pay band:

Provided that the third increment under this rule shall be granted retrospectively from the prescribed date of increment after passing the prescribed departmental examination, or the last of the prescribed departmental examinations, as the case may be, on the successful completion of the probation and confirmation:

Provided further that a direct recruit who has been exempted from appearing for the whole or any part of the departmental examination or examinations, as the case may be, for the reason that he had already passed such examination or examinations or part thereof before he became a member of the Service, shall, for the purpose of this rule, be deemed to have passed the departmental examination or examinations or part thereof, as the case may be, from the date

of the earliest such examination, examinations or part thereof, in which he would have appeared, but for the exemption, after he became a member of the Service.”.

9. In rule 11 of the said rules, in sub-rule (7), for the letters and figures “Rs.24050-650-26000” the letters, figures and words “Rs.75500-(annual increment @ 3%)-80000” shall be substituted.
10. In Schedule –I of the said rules,
  - (a) for the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of January, 1996”, wherever they occur, shall be substituted by the figures, letters and words “1<sup>st</sup> day of January, 2006”;
  - (b) for paragraph (1), the following paragraph shall be substituted, namely;
 

“(1) Notwithstanding anything contained in the first proviso to sub-rule (1) of rule 3, and the Notes thereunder, the initial pay of a promoted officer or an officer appointed by selection, as the case may be, shall be fixed at the pay drawn by the officer in the pay band-3 or pay band-4 in the State Service in addition to one of the grade pays admissible for the three components of Senior Scale as per the eligibility of the officer in the following manner, namely:-

<u>Pay in Pay Band</u>	<u>Grade Pay</u>
Officers with pay up to Rs.28280 in Pay Band -3	Rs.6600
Officers with pay between Rs.28281 to Rs.30690 in Pay Band -3	Rs.7600
Officers with pay Rs.30691 or above In Pay Band -3 or Pay-Band-4	Rs.8700

In case the pay of officer in State Service has not been revised to the new pay structure with effect from the 1<sup>st</sup> day January, 2006, the same shall be revised in terms of provisions contained in rule 4.”

11. In Schedule –II, A of the said rules, one of the existing posts of Director General of Police in the HAG+ scale of Rs.75500-(annual increment @ 3%)-80000, in the following States, shall be placed in the Apex scale of Rs.80000 (fixed) and designated as the head of police force in the State or Union Territory, as follows, namely:-

<u>State</u>	<u>Designation of post</u>	<u>Apex Scale</u>
(1)	(2)	(3)
Andhra Pradesh	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000(fixed)
Delhi (UT)	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000(fixed)
Assam	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000(fixed)
Meghalaya	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000(fixed)
Bihar	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Chhattisgarh	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)

Gujarat	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Haryana	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Himachal Pradesh	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Jammu and Kashmir	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Jharkhand	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Karnataka	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Kerala	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Madhya Pradesh	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Maharashtra	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Manipur	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Tripura	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Nagaland	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Orissa	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Punjab	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Rajasthan	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Tamil Nadu	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Uttaranchal	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
Uttar Pradesh	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)
West Bengal	Director General of Police (head of police force)	Rs. 80,000 (fixed)

12. In Schedule-II.A and II.C of the said rules,

- for the words "Pay or Scale of Pay" the following shall be substituted namely:-  
"Pay or Pay-Scale or Pay Band + Grade Pay,";
- for the letters figures and words "Rs. 26000", "Rs.24050-650-26000", "Rs.22400-525-24500", "Rs.18400-500-22400", "Rs.16400-450-20000", wherever they occur, the letters figures and words "Rs.80000", "Rs.75500-(annual increment @ 3%)-80000", "Pay Band-4: Rs.37400-67000; plus Grade Pay Rs.12000", "Pay Band-4: Rs.37400-67000; plus Grade Pay Rs.10000", "Pay Band-4: Rs.37400-67000; plus Grade Pay Rs.8900" shall respectively be substituted.

13. In the Schedule II-C, :-

- at Serial No. 6, under the Column (4), for the entry relating to the post of Director General, Indo-Tibetan Border Police, the following entry shall be substituted, namely:-  
"Rs.80000 (fixed)";
- after Serial No. 12; the following shall be inserted, namely:-  
"12.a Sashstra Seema Bal - Director General - Rs.80000(fixed)";
- under Column (5) relating to Central (Deputation as Tenure) Allowance, for the letters and figures "Rs.1000, Rs.800 and Rs.400", wherever they occur, the words "Ten percent of the basic pay subject to the maximum of rupees four thousand per mensem" shall be substituted;
- for Note 1 and Note 2 occurring at the end of Schedule II-C, the following shall be substituted, namely:-  
'Note :- The Central (Deputation on Tenure) Allowance specified in this rule shall be paid to a member of the Service for the period of deputation approved by the competent authority.'

14. for "II.D— Posts under the Central Government when held by member of the Service and the table" under Schedule II, the following TABLE shall be substituted, namely:-  
"II.D— Posts under the Central Government when held by member of the Service:

TABLE

Name of Post (1)	Scale of Pay (2)	Central (Deputation on Tenure) Allowance (3)
(1) Secretary to the Government of India or Special Secretary to the Government of India	Rs.80000 (Fixed)	---
(2) Additional Secretary to the Government of India	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.12000	---
(3) Joint Secretary to the Government of India	Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.10,000	---

(4) Director to the Government of India	Selection Grade: (Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.8,700 )	Ten percent of the basic pay subject to the maximum of rupees four thousand per mensem.
(5) Deputy Secretary to the Government of India	Selection Grade: (Pay Band-4: Rs.37400-67000; and Grade Pay Rs.8,700 ) or Junior Administrative Grade: Pay Band-3: Rs.15600-39100; and Grade Pay Rs.7600	Ten percent of the basic pay subject to the maximum of rupees four thousand per mensem.
(6) Under Secretary to the Government of India	Junior Administrative Grade: Pay Band-3: Rs.15600-39100; and Grade Pay Rs.7600 or Senior Time Scale (Grade: Pay Band-3: Rs.15600-39100; and Grade Pay Rs.6600)	Ten percent of the basic pay subject to the maximum of rupees four thousand per mensem.

**Note 1**—The Central (Deputation on Tenure) Allowance specified in this rule shall be paid to a member of the Service for the period of deputation approved by the competent authority.”

[F.No.14021/4/2008-AIS(II)]

HARJOT KAUR, Director (Services)

**Note** : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 108(E), dated the 21<sup>st</sup> February, 2008.

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to implement the recommendations made by the Sixth Central Pay Commission with the modification approved by the Government as contained in Government of India resolution No. 1/1/2008-IC, dated 29<sup>th</sup> August, 2008 relating to revision of pay-scales in respect of the All India Services with effect from the 1<sup>st</sup> January, 2006. With a view to implement those recommendations, the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007 are being amended accordingly with effect from the 1<sup>st</sup> January, 2006.

It is certified that no member of the Indian Police Service is likely to be adversely affected by giving retrospective effect to these rules.